

करने से क्षेत्र की स्वदेशी और आदवासी आबादी की सुरक्षा सुनिश्चिती होगी ।

आगे की राह

- इसके बारे में नयियों की अधसूचना, जसिके बनिा कानून लागू नहीं कयिा जा सकता है, सरकार की ओर से कोई प्रतबिद्धता न होने के कारण लंबति है ।
- इस प्रकार गृह मंत्रालय को चाहिये कविह CAA नयियों को अत्यंत पारदर्शिता के साथ अधसूचिती करे तथा इससे जुड़ी आशंकाओं को दूर करे ।

यूपीएससी सविलि सेवा परीक्षा वगित वर्षों के प्रश्न (PYQs):

प्रश्न:भारतीय संवधान में पाँचवी अनुसूची और छठी अनुसूची के प्रावधान संबंधति हैं:(2015)

- (a) अनुसूचिती जनजातयियों के हतियों की रक्षा करना
- (b) राज्यों के बीच की सीमाओं का नरिधारण
- (c) पंचायतों की ज़मिमेदारी, शक्तयियों, अधिकार का नरिधारण
- (d) सभी सीमावर्ती राज्यों के हतियों की रक्षा करना

उत्तर: (a)

- पाँचवी अनुसूची असम, मेघालय, त्रपुरा और मज़ोरम के अलावा अन्य राज्यों में अनुसूचिती क्षेत्रों व अनुसूचिती जनजातयियों के प्रशासन एवं नयित्रण के लयि प्रावधान करती है ।
- छठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रपुरा और मज़ोरम में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधति है ।

स्रोत: इंडयिन एक्सप्रेस

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/mha-on-citizenship-amendment-act-2019>

